To Redress the Issue of Scarcity of Fodder

56 Sh. Varun Chaudhary (Mulana)

Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state:

a) The year wise budget estimate, revised estimate and actual expenditure of Gau Aayog for the last three years alongwith the current year expenditure till January, 2024;

b) Whether any survey has been done to fix the capacity of Gaushala/Nandishala as per space availability; if not, reasons thereof; and

c) The steps taken by the Government to redress the issue of scarcity of fodder together with details thereof?

Jai Parkash Dalal, Animal Husbandry & Dairying Minister

a) The details of reply are given below: -

Unspent Budget of Previous FY (Rs. In Lacs.)	Financial Year	Budget Allotted to Gau Aayog (Rs. In Lacs.)	Other receipts (Rs. In Lacs.)	Total (Rs. In Lacs.)	Expenditure of Gau Aayog (Rs. In Lacs.)	Balance (Rs. In Lacs.)
1048.20	2020-21	Nil	116.67	1164.87	1052.68	112.19
112.19	2021-22	300.00	3.86	416.06	201.25	214.80
214.80	2022-23	300.00	5.11	519.91	258.26	261.64
261.64	2023-24 (Till January, 2024)	3600.00	1.96	3863.60	3423.50	440.10

b) No Sir, no such survey has been done by Haryana Gau Seva Aayog. These Gaushalas are being run by NGOs and Gaushala Management Committee accommodates the cattle as per space availability & feasibility of Gaushalas.

c) This point pertains to Department of Farmer Welfare & Agriculture Haryana. The concerned Department has submitted the reply as below:

Under *Chara Bijai Yojna* for the last year 2022-23, total area of 795.33 acre was verified by the different districts and as such a total amount of Rs. 79,53,300/- as incentive @ Rs. 10,000 per acre was provided to the farmers. However, the said *Yojna* is not implemented for the current year 2023-24 by this Department.

चारे की कमी की समस्या का समाधान करना

56 श्री. वरुण चौधरी (मुलाना):

क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे कि:

क) गत 3 वर्षों का गौ आयोग का वर्षवार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक खर्चे क्या हैं तथा वर्तमान वर्ष में जनवरी, 2024 तक खर्च कितना है;

ख) क्या स्थान की उपलब्धता के अनुसार गौशाला/नंदीशाला की क्षमता निर्धारित करने के लिए कोई सर्वे किया गया है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; तथा

ग) सरकार द्वारा चारे की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए क्या पग उठाए गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

जय प्रकाश दलाल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री

क) उत्तर का विवरण नीचे दिया गया है:

पिछले वित्त वर्ष का अव्ययित बजट (लाख रुपये में)	वित्त वर्ष	गौ आयोग को आवंटित वित्तीय वर्ष का बजट (लाख रुपये में)	अन्य प्राप्तियां (लाख रुपये में)	कुल (लाख रुपये में)	गौ आयोग का व्यय (लाख रुपये में)	शेष राशि (लाख रूपये में
1048.20	2020-21	शून्य	116.67	1164.87	1052.68	112.19
112.19	2021-22	300.00	3.86	416.06	201.25	214.80
214.80	2022-23	300.00	5.11	519.91	258.26	261.64
261.64	2023-24 (जनवरी 2024 तक)	3600.00	1.96	3863.60	3423.50	440.10

ख) नहीं श्रीमान, हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है। ये गौशालाएं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हैं और गौशाला प्रबंधन समिति गौशालाओं मे जगह की उपलब्धता और व्यवहार्यता के अनुसार गौवंश को समायोजित करती है।

ग) यह बिंदु किसान कल्याण एवं कृषि विभाग हरियाणा से जुड़ा है। संबंधित विभाग ने निम्नानुसार उत्तर प्रस्तुत किया हैः

पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान चारा बिजाई योजना के तहत विभिन्न जिलों द्वारा कुल 795.33 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया और किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की दर से कुल रूपये 79,53,300/- की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई। हालाँकि, उक्त योजना इस विभाग द्वारा चालू वर्ष 2023-24 के लिए लागू नहीं की गई है।